

कृषि क्षेत्र के लिए बजट सकारात्मक : सभरवाल

नई दिल्ली 24 जुलाई (एजेसिया)। कृषि क्षेत्र के लिए बजट में व्यापक और विकासोन्मुख दृष्टिकोण है, ये अपेक्षित था। जो इस क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए है। 2024-25 के बजट में कृषि क्षेत्र पर जोर उद्योग और उसके सहयोगी संगठनों के लिए एक स्वागत योग्य प्रोत्साहन है। इस क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें धन का एक बड़ा हिस्सा दालों और तिलहन जैसी कुछ वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग में सुधार के लिए है। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, संदीप सभरवाल, ग्रुप सीईओ, सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड कहते हैं कि इसके अतिरिक्त, सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए, बजट में प्रमुख उपभोग केंद्रों के पास बड़े पैमाने पर उत्पादन क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव है। इस पहल का उद्देश्य परिवहन और वितरण लागत को कम करके आपूर्ति-श्रृंखला प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित और कुशल बनाना है। साथ ही बेहतर बुनियादी ढांचे से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी जो वर्तमान में इस क्षेत्र की प्रमुख चिंताओं में से एक है, विशेषकर सब्जी उत्पादकों के लिए। आपूर्ति श्रृंखला दक्षता और भंडारण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और निजी प्लेयर के साथ सहयोग करने की सरकार की प्रतिबद्धता आशावादी है। इन संगठनों को बढ़ावा देकर, किसान इनपुट, प्रौद्योगिकी और बाजार संपर्क तक बेहतर पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और प्रॉफिटेबिलिटी में और सुधार हो सकता है। कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास में सरकार की पहल बजट के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाती है। हम एक डिजिटल युग में रह रहे हैं जहां 'फिजिटल' इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल करने की कुंजी है।



विराट वैभव

कृषि क्षेत्र के लिए बजट सकारात्मक : संदीप सभरवाल

एअेंसी ■ नई दिल्ली

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड के ग्रुप सीईओ संदीप सभरवाल ने कहा, कृषि क्षेत्र के लिए बजट में व्यापक और विकासोन्मुख दृष्टिकोण है, ये अपेक्षित था। जो इस क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए है। 2024-25 के बजट में कृषि क्षेत्र पर जोर उद्योग और उसके सहयोगी संगठनों के लिए एक स्वागत योग्य प्रोत्साहन है। इस क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें धन का एक बड़ा हिस्सा दालों और तिलहन

के उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग में सुधार के लिए है। इसके अतिरिक्त, सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए, बजट में प्रमुख उपभोग केंद्रों के पास बड़े पैमाने पर उत्पादन क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव है।

इस पहल का उद्देश्य परिवहन और वितरण लागत को कम करके आपूर्ति-श्रृंखला प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित और कुशल बनाना है। साथ ही बेहतर बुनियादी ढांचे से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी जो वर्तमान में इस क्षेत्र की प्रमुख चिंताओं में से एक है, विशेषकर सब्जी उत्पादकों के लिए।

कृषि क्षेत्र के लिए बजट अनुकूल : संदीप सभरवाल

नई दिल्ली। कृषि क्षेत्र के लिए बजट में व्यापक और विकासोन्मुख दृष्टिकोण है, ये अपेक्षित था। इस क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए है। 2024-25 के बजट में कृषि क्षेत्र पर जोर उद्योग और उसके सहयोगी संगठनों के लिए एक स्वगत योग्य प्रोत्साहन है। इस क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें धन का एक बड़ा हिस्सा कृषि और वितरण जैसे कुछ तत्वों के उत्पादन, भंडारण और संचालन में सुधार के लिए है। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, संदीप सभरवाल, युप सीईओ, सोहन लाल कर्मोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड कहते हैं कि इसके अतिरिक्त, सभी अपूर्ति-संरचनाओं



को मजबूत करने के लिए, बजट में प्रमुख उपयोग केंद्रों के पास बड़े पैमाने पर उत्पादन क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव है। इस पहल का उद्देश्य परिवहन और वितरण लागत को कम करने के लिए अपूर्ति-संरचना प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित और कुशल बनाना है। साथ ही बेहतर बुनियादी ढांचे से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी जो वर्तमान में इस क्षेत्र की प्रमुख चिंताओं में से एक है।

विशेषकर सभी उत्पादकों के लिए अपूर्ति-संरचना एकात्मक और भंडारण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और निजी प्लेयर के साथ सहयोग करने की सरकार की प्रतिबद्धता असाधारण है। इन संगठनों को बढ़ावा देकर, किसान इनपुट, प्रौद्योगिकी और बाजार संपर्क तक बेहतर पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और प्रतिक्रियाशीलता में और सुधार हो सकता है। कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास में सरकार की पहल बजट के प्राथमिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। हम एक डिजिटल युग में रह रहे हैं जहां डिजिटल इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसीलिए, डिजिटल और

डिजिटल दोनों बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने से क्षेत्र के विकास में काफी हद तक योगदान मिलेगा। कुल मिलाकर इससे किसानों की आय और आयव्यय में सुधार करने में मदद मिलेगी। लेकिन जहाँ ये बचने के लिए कड़े नियंत्रण प्रणाली के तहत खर्च देने का काम सरकारों से किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर, कुछ अपवादों को छोड़कर, बजट महत्वपूर्ण मुद्दों को एहसास करने के लिए इतने के साथ एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हम कृषि को प्राथमिकता देने के सरकार के प्रयासों को सराहना करते हैं और क्षेत्र को बुद्धि और विकास में योगदान देने के लिए तैयार हैं। संदीप सभरवाल, युप सीईओ, सोहन लाल कर्मोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड ने कहा।



कृषि क्षेत्र के लिए बजट सकारात्मक : संदीप सभरवाल

नई दिल्ली। (बीओ)। कृषि क्षेत्र के लिए बजट में व्यापक और विकासोन्मुख दृष्टिकोण है, ये अपेक्षित था। इस क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए है। 2024-25 के बजट में कृषि क्षेत्र पर जोर उद्योग और उसके सहयोगी संगठनों के लिए एक स्वगत योग्य प्रोत्साहन है। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, संदीप सभरवाल, युप सीईओ, सोहन लाल कर्मोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड कहते हैं कि इसके अतिरिक्त, सभी अपूर्ति-संरचनाओं को मजबूत करने के लिए, बजट में प्रमुख उपयोग केंद्रों के पास बड़े पैमाने पर उत्पादन क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव है। इस पहल का उद्देश्य परिवहन और वितरण लागत को कम करके अपूर्ति-संरचना प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित और कुशल बनाना है। साथ ही बेहतर बुनियादी ढांचे से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी जो वर्तमान में इस क्षेत्र की प्रमुख चिंताओं में से एक है। विशेषकर सभी उत्पादकों के लिए, अपूर्ति-संरचना दक्षता और भंडारण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और निजी प्लेयर के साथ सहयोग करने की सरकार की प्रतिबद्धता आशावादी है। इन संगठनों को बढ़ावा देकर, किसान इनपुट, प्रौद्योगिकी और बाजार संपर्क तक बेहतर पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और प्रतिक्रियाशीलता में और सुधार हो सकता है। कृषि के लिए डिजिटल

सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास में सरकार की पहल बजट के प्राथमिक दृष्टिकोण को दर्शाती है।